RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 25 अप्रैल से 01 मई 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-89 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

Big Boost for MSMEs: India–Korea Alliance Strengthens, PM Vishwakarma at the Centre of Sustainable Growth

MoU signed to boost technology, innovation and market access as special session highlights grassroots entrepreneurship

New Delhi: India and the Republic of Korea have taken a significant step to strengthen economic cooperation by signing a Memorandum of Understanding (MoU) in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. The agreement aims to enhance collaboration in areas such as technology transfer, startup support, skill development, capacity building, and market access for small businesses in both countries.

The MoU reflects the growing strategic partnership between the two nations and recognizes the vital role MSMEs play in employment generation, exports, and inclusive economic growth. By sharing best practices and encouraging joint ventures, both sides hope to empower entrepreneurs, improve competitiveness, and promote innovation-driven growth.

Alongside this development, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises organized a special breakaway session on "Sustainable Livelihood through PM Vishwakarma." The session focused on empowering traditional artisans and craftspeople by providing them with financial assistance, skill upgradation, modern toolkits, digital training, and easier credit access under the PM Vishwakarma scheme.

Officials emphasized that strengthening grassroots enterprises is essential for building a self-reliant and resilient economy. The initiative aims to formalize traditional occupations, improve product quality, and connect artisans to national and global markets through e-commerce and branding support.

Experts noted that combining international cooperation with domestic livelihood schemes can create a multiplier effect for India's MSME ecosystem. While global partnerships bring technology and investment, schemes like PM Vishwakarma ensure that the benefits reach local communities and traditional workers.

Together, these efforts underline India's commitment to inclusive growth, innovation, and sustainable development in the MSME sector.

निवेश का नया रिकॉर्ड: एमपी में दो साल में 7,800 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश

यूके, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की कंपनियां आगे बढ़ीं, पांच जिलों में भूमि आवंटन और शुरुआती कार्य शुरू

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में लगभग 7,800 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित किया है। राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों और तेज स्वीकृति प्रक्रिया के कारण छह वैश्विक कंपनियां अब जमीन आवंटन और प्रारंभिक चरण के कार्यान्वयन की ओर बढ़ रही हैं। ये कंपनियां यूके, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया से हैं तथा निवेश पांच जिलों में फैला हुआ है।

यह FDI वास्तविक रूप से जमीन पर उतर रहा है, जो राज्य की बढ़ती निवेशक विश्वसनीयता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने उद्योग जगत को आकर्षित करने के लिए कई सुधार किए हैं,

जिसमें एकल खिड़की प्रणाली, आसान अनुमोदन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में शामिल हो रहा है।

निवेश मुख्य रूप से विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और संबंधित क्षेत्रों में आया है। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावना है। विशेष रूप से इंदौर समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों

में अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। राज्य की रणनीतिक स्थिति, कुशल कार्यबल और सुधारित बिजनेस इकोसिस्टम विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह FDI न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और

युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। सरकार

का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में FDI के आंकड़े और बढ़ें तथा मध्य प्रदेश को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाया जाए।

इस उपलब्धि से राज्य की प्रगति स्पष्ट है। यदि यही गति बनी रही तो मध्य प्रदेश भारत के तेजी से बढ़ते औद्योगिक राज्यों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

भारतीय धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: अमेज़न ने 30 मिलियन डॉलर के कार्बन क्रेडिट खरीदे

ग्रीन राइस एलायंस के साथ समझौता, 13,000 से अधिक छोटे किसानों को आय और जलवायु संरक्षण का दोहरा लाभ

नई दिल्ली: वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न ने भारतीय चावल किसानों से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए 30 मिलियन डॉलर (लगभग 280 करोड़ रुपये) का बड़ा समझौता किया है। यह भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा कार्बन क्रेडिट सौदा है और वैश्विक स्तर पर भी कृषि कार्बन क्रेडिट के मामले में प्रमुख सौदों में शामिल है।

यह समझौता गुड राइस एलायंस के साथ किया गया है, जो बायर, सिंगापुर की टेमासेक की जेनजीरो और शेल नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस द्वारा समर्थित है। इस पहल के तहत 13,000 से अधिक छोटे किसानों को शामिल किया जाएगा, जो देशभर में लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर काम कर रहे हैं।

परंपरागत चावल की खेती में लगातार पानी भरने से मीथेन गैस का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। गुड राइस एलायंस किसानों को वैकल्पिक खेती के तरीके जैसे वैकल्पिक गीली-सूखी (AWD) विधि, बेहतर बीज और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे मीथेन उत्सर्जन में काफी कमी आती है। इससे उत्पन्न कार्बन क्रेडिट अमेज़न खरीदेगी।

इस सौदे से कुल 6,85,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (CO_2) उत्सर्जन को ऑफसेट करने की उम्मीद है। अमेज़न अपनी क्लाइमेट प्लेज के तहत 2040 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में यह कदम उठा रही है।

किसानों के लिए यह सौदा अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा। उन्हें बेहतर खेती प्रथाओं के लिए प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे फसल की पैदावार बढ़ सकती है और पानी की बचत भी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अनूठा उदाहरण है।

यह समझौता कॉर्पोरेट्स द्वारा कृषि-आधारित कार्बन क्रेडिट पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। यदि सफल रहा तो भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में ऐसे और सौदे हो सकते हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

भारत को बड़ी राहत: ICT टैरिफ पर भारत-ताइवान आमने-सामने, फैसला अक्टूबर तक टला

WTO ने दोनों देशों की संयुक्त अपील स्वीकार की, आपसी बातचीत से समाधान की उम्मीद

नई दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद निपटान निकाय (DSB) ने भारत और ताइवान की संयुक्त अपील पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों पर भारत के आयात शुल्क से संबंधित फैसले को 27 अक्टूबर 2026 तक टाल दिया है। दोनों देश इस विवाद को आपसी चर्चा के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह विवाद 2019 में ताइवान (चाइनीज ताइपे) द्वारा भारत पर WTO में लाया गया था। ताइवान का आरोप है कि भारत ने कुछ ICT उत्पादों जैसे मोबाइल फोन, टेलीकॉम उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (ITA-1) के तहत शुल्क मुक्त सुविधा का उल्लंघन किया है। पैनल रिपोर्ट 2023 में जारी हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों की बार-बार अपील पर फैसले को कई बार स्थगित किया जा चुका है। यह नवीनतम स्थगन नौवां है।

भारत का तर्क है कि उसके टैरिफ संबंधी उपाय ITA-1 के दायरे में नहीं आते और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं। दोनों देश द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। यदि अक्टूबर तक कोई समझौता नहीं हुआ तो WTO पैनल रिपोर्ट को अपनाया जा सकता है, जिससे भारत पर दबाव बढ़ सकता है।

यह देरी दोनों देशों को व्यापार संबंध मजबूत करने और आपसी हितों का समाधान निकालने का मौका देगी। ICT क्षेत्र में भारत-ताइवान सहयोग से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आपसी समझौता ही सबसे अच्छा रास्ता है।

Nippon India Mutual Fund Launches 'Har Ghar Investor' Campaign to Boost Retail Participation

Multi-phase initiative aims to make mutual funds accessible to every Indian household and promote disciplined long-term investing

Mumbai: : Nippon India Mutual Fund (NIMF) has rolled out a major investor awareness campaign titled 'Har Ghar Investor' to significantly increase retail participation in mutual funds across the country.

The campaign seeks to educate and empower first-time investors, instil confidence, and encourage disciplined investing habits. In its initial phase, the initiative aims to ensure that at least one member in every household starts investing in mutual funds, with a long-term vision of broader financial inclusion.

NIMF officials stated that the campaign focuses on simplifying the investment journey through educational content, workshops, digital outreach, and on-ground engagement programmes. It addresses common barriers such as lack of awareness, fear of market volatility, and misconceptions about mutual funds.

With India's mutual fund industry witnessing rapid growth driven by systematic investment plans (SIPs) retail investors have already shown strong interest. However, a large section of the population, especially in Tier-2 and Tier-3 cities and rural areas, still remains untouched. 'Har Ghar Investor' is designed to bridge this gap by using simple language, relatable examples, and digital tools to explain concepts like rupee-cost averaging, asset allocation, and the power of compounding.The campaign will run across multiple channels including television, social media, print, and community events. It will also feature investor testimonials and expert sessions to build trust.

Sundeep Sikka, CEO & Executive Director of Nippon India Mutual Fund, emphasised that the real milestone is not just increasing numbers but building sustainable financial awareness for the future. “We want every Indian family to view mutual funds as a reliable tool for wealth creation,” he said.

Industry experts view this move as timely, as it aligns with the government’s push for financial literacy and inclusive growth. If successful, the campaign could further accelerate retail inflows into mutual funds and strengthen India’s position as one of the fastest-growing mutual fund markets globally.

Analysts believe such proactive investor education initiatives will play a crucial role in deepening market penetration and fostering a culture of long-term investing among millions of new participants.

किसानों को सस्ती बिजली और सोलर पंप: सीएम मोहन यादव का बड़ा निर्देश

चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप से जोड़ने का लक्ष्य, नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं को तेज करने का आदेश

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को सोलर पंप अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इच्छुक किसानों को पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

सीएम यादव ने स्पष्ट किया कि किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने की दिशा में काम किया जाए, ताकि कृषि उत्पादकता बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक दो लाख

से अधिक किसानों को सोलर पंप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को भी तेज गति से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बिजली महंगी बोझ नहीं, बल्कि सहायक साधन बने। सोलर पंपों से बिजली के बिल में भारी कमी आएगी, सिंचाई सुविधा बढ़ेगी और डीजल-बिजली पर निर्भरता घटेगी। सरकार किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान मात्र 10% राशि देकर पंप लगा सकेंगे। भविष्य में अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदने की भी योजना है।

इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अधिकारी समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू करें, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों।

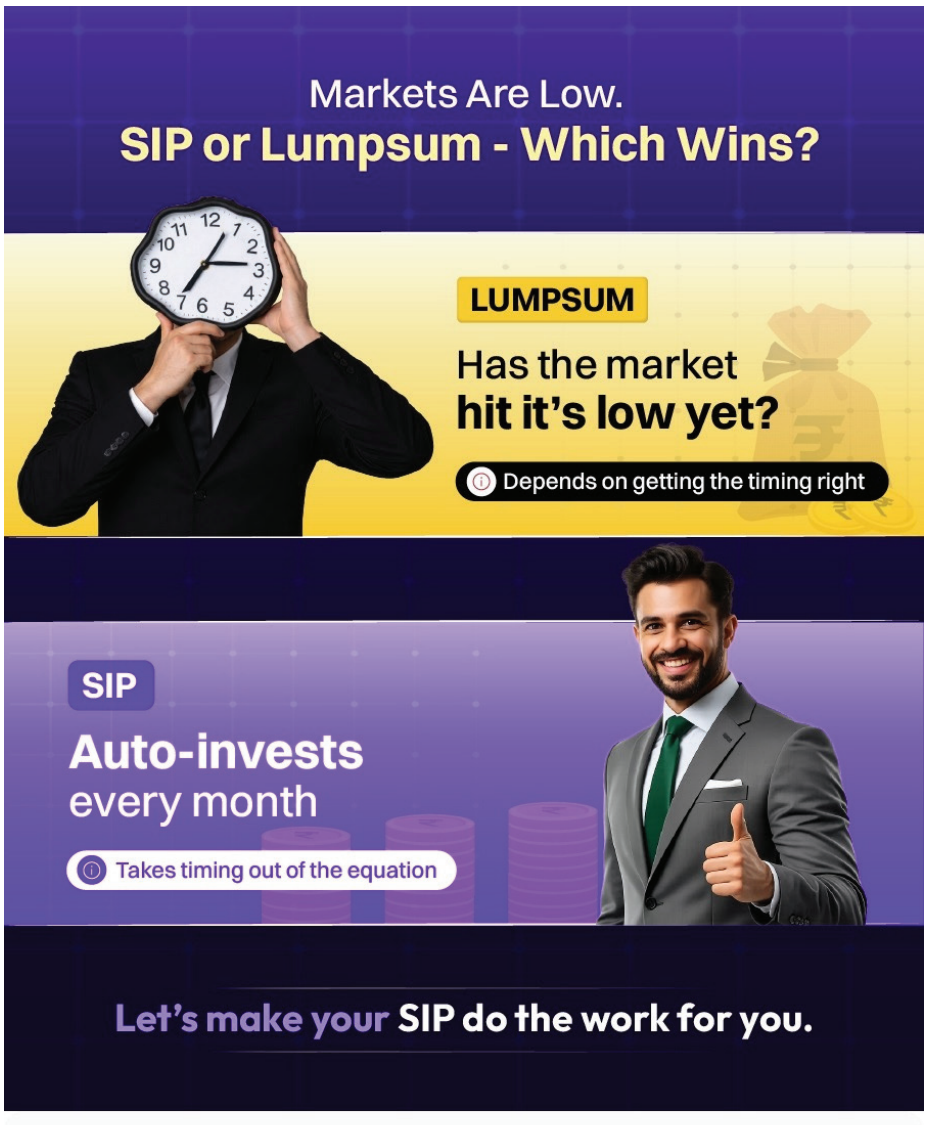

यह कदम मध्य प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर पंपों के व्यापक उपयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ सकती है और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार का फोकस साफ है सस्ती बिजली, स्वच्छ ऊर्जा और समृद्ध किसान।

Gold ETFs Shine Bright: Net Inflows Jump 4.5x in FY26 Amid Volatility

Record ₹68,867 crore flows into gold exchange-traded funds as investors seek safe haven amid geopolitical tensions and market volatility

Bhopal: Gold exchange-traded funds (ETFs) in India witnessed an unprecedented boom in FY26, with net inflows skyrocketing to a record ₹68,867 crore. This represents a staggering 364 per cent year-on-year jump or more than 4.5 times the previous year's inflows making gold ETFs the fastest-growing category across the entire mutual fund industry, according to data from the Association of Mutual Funds in India (AMFI).

The surge has dramatically increased gold ETFs' share of overall mutual fund inflows to nearly 10 per cent, well above the historical average of 1-3 per cent. Investors poured money into these passive instruments as a hedge against heightened geopolitical risks, stock market volatility, and uncertainty in global financial markets.

Gold prices remained elevated throughout the year, supported by central bank buying and safe-haven demand. Domestic investors, traditionally inclined towards physical gold, increasingly turned to gold ETFs for their convenience, lower costs, transparency, and ease of trading on stock exchanges. Unlike physical gold, ETFs eliminate concerns related to storage, purity, and security while offering liquidity similar to equities.

Industry experts attribute the massive inflows to a combination of factors: persistent global tensions, a volatile equity market that prompted portfolio rebalancing, and growing awareness about gold's role in diversification. Several fund houses, including Nippon India ETF Gold BeES, saw significant traction, further boosting overall assets under management in the gold ETF segment.

This shift signals a maturing investor base that values regulated financial products over traditional forms of gold investment. However, analysts caution that while gold ETFs provide an excellent tactical allocation tool, investors should maintain a balanced portfolio and avoid overexposure. The remarkable performance of gold ETFs in FY26 underscores gold's enduring appeal as a portfolio protector in uncertain times and highlights the rapid evolution of India's mutual fund industry. With continued global uncertainties likely, gold ETFs may continue to attract steady interest in the coming quarters.

GST Exemption Boosts Life Insurance Premiums to Record ₹4.6 Lakh Crore; 16% Growth in FY26

New business premium hits record ₹4.60 lakh crore as GST exemption boosts demand for protection and savings plans

Bhopal: India's life insurance industry recorded a robust 16% year-on-year growth in new business premium (NBP) during FY26, reaching a record ₹4.60 lakh crore. This marks a significant acceleration compared to previous years and reflects renewed momentum in the sector, according to industry data.

The growth was primarily driven by the government's decision to exempt individual life insurance policies from Goods and Services Tax (GST), effective from September 2025. The removal of the 18% GST made policies more affordable, triggering strong customer demand, especially for pure protection products such as term insurance. Both public and private players benefited, with private insurers posting slightly higher growth at around 17% compared to LIC's 15%.

Insurers also strategically shifted focus towards high-margin products, including protection-oriented plans, unit-linked insurance plans (ULIPs) with better features, and long-term savings solutions. This move helped improve product mix and supported value creation despite some margin pressures arising from the loss of input tax credits following the GST exemption.

Life Insurance Corporation of India (LIC) maintained its dominant position with NBP of approximately ₹2.60 lakh crore, while the 26 private life insurers collectively crossed ₹1.99 lakh crore. Key private players like SBI Life, HDFC Life, and ICICI Prudential Life reported healthy growth, aided by digital distribution channels and innovative product offerings.

The number of policies sold also rose by nearly 5%, indicating broader penetration. Industry experts believe the GST relief has made insurance more accessible to middle-class families, while the emphasis on high-margin products is expected to support long-term profitability.

However, analysts caution that the loss of input tax credits may exert pressure on value of new business (VNB) margins in the near term. Despite this, the structural drivers rising financial awareness, digital adoption, and increasing protection needs remain strong.

The impressive performance in FY26 underscores the resilience of India's life insurance sector and its growing role in household financial planning. With continued focus on customer-centric products and distribution expansion, the industry is well-positioned for sustained double-digit growth in the coming years.

अदाणी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कदम बढ़ाया, नई न्यूक्लियर इकाई गठित

रावतभाटा-राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड की स्थापना, भारत के 100 गीगावॉट न्यूक्लियर लक्ष्य में योगदान की तैयारी

अदाणी पावर लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए एक नई कंपनी का गठन किया है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड (AAEL) ने 20 अप्रैल 2026 को रावतभाटा-राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड (RRAEL) नाम से एक स्टेप-डाउन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया।

नई कंपनी का मुख्य उद्देश्य परमाणु और एटॉमिक ऊर्जा से प्राप्त बिजली का उत्पादन, संचरण और वितरण करना है। इस कदम से अदाणी पावर अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो को विविधीकरण करने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार करने की रणनीति को आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी।

भारत सरकार ने 2047 तक न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वर्तमान में देश की न्यूक्लियर क्षमता मात्र 8-9 गीगावॉट के आसपास है। अदाणी ग्रुप का यह कदम सरकार की नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो सकता है।

अदाणी पावर वर्तमान में देश की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 12,410 मेगावॉट से अधिक है। हाल के वर्षों में कंपनी ने सोलर और अन्य नवीकरणीय स्रोतों में भी भारी निवेश किया है। न्यूक्लियर आर्म के गठन से कंपनी भविष्य में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर प्लांट विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अदाणी पावर को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा। हालांकि, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में नियामकीय मंजूरी, सुरक्षा मानकों और भारी पूंजी निवेश की चुनौतियां भी हैं।

यह विकास भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

L&T Energy GreenTech Signs Long-Term Green Ammonia Supply Deal with Japan's ITOCHU

300,000 tonnes per annum offtake agreement to fuel Singapore's maritime decarbonisation from Gujarat facility

Mumbai: L&T Energy GreenTech Ltd (LTEG), a wholly-owned subsidiary of Larsen & Toubro, has signed a long-term green ammonia supply agreement with Japan's leading trading house ITOCHU Corporation. The deal marks a significant milestone in India's green hydrogen and ammonia ecosystem and strengthens bilateral cooperation in clean energy between India and Japan.

Under the agreement, LTEG will supply up to 300,000 tonnes per annum (KTPA) of green ammonia from its proposed production facility at Kandla in Gujarat. ITOCHU will offtake the entire volume primarily for bunkering applications in Singapore, supporting the shipping industry's transition to low-carbon fuels.

Green ammonia, produced using renewable energy and green hydrogen, is emerging as a zero-emission marine fuel. It offers a practical solution for decarbonising international shipping, one of the hardest-to-abate sectors. The Kandla project leverages Gujarat's strategic location, excellent port infrastructure, and abundant renewable energy potential.

This partnership builds on an earlier Joint Development Agreement signed in 2025. It combines L&T's engineering expertise and project execution capabilities with ITOCHU's global trading

network and expertise in energy markets. The collaboration aims to create a reliable supply chain for green ammonia across key maritime routes.

Industry analysts view the deal as a boost for India's ambition to become a global green hydrogen and ammonia hub. It will help attract further investments, create employment opportunities, and support India's net-zero goals. For ITOCHU, the arrangement advances itsstrategy to build a global low-carbon ammonia supply ecosystem, with Singapore as a key bunkering hub.

The long-term offtake provides revenue visibility to LTEG and de-risks the project. Both companies expressed confidence that this initiative will accelerate the adoption of green fuels in international shipping.

एलआईसी की नई जीवन शांति: जीवन भर की गारंटीड मासिक आय का भरोसा

एक बार निवेश, आजीवन पेंशन — रिटायरमेंट की चिंता खत्म

भोपाल: जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपनी लोकप्रिय पेंशन योजना का नया संस्करण पेश किया है —नई जीवन शांति। यह सिंगल प्रीमियम डिफर्ड एन्युटी प्लान उन लोगों के लिए आदर्श है जो एक बार निवेश करके जीवन भर गारंटीड मासिक आय चाहते हैं। इस योजना में आपको एकमुश्त राशि जमा करनी होती है और चुने गए डिफरमेंट पीरियड के बाद से हर महीने निश्चित पेंशन मिलती रहती है चाहे जितनी उम्र हो जाए।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- सिंगल प्रीमियम: न्यूनतम खरीद मूल्य ₹1.50 लाख (कुछ मामलों में कम भी संभव)। अधिकतम सीमा नहीं।
- दो विकल्प: सिंगल लाइफ (एक व्यक्ति के लिए) और जॉइंट लाइफ (पति-पत्नी या परिवार के सदस्यों के लिए)।
- डिफरमेंट पीरियड: 1 से 12 वर्ष तक चुन सकते हैं। इस दौरान कोई पेंशन नहीं, लेकिन पॉलिसी शुरू होते ही एन्युटी रेट गारंटीड हो जाता है।
- पेंशन मोड: मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक। न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000।
- मृत्यु लाभ: डिफरमेंट पीरियड में मृत्यु होने पर खरीद मूल्य वापस या एन्युटी के रूप में विकल्प। पेंशन शुरू होने के बाद अंतिम उत्तरजीवी तक पेंशन जारी रहती है।

यह योजना नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग है, अर्थात लाभ पूरी तरह गारंटीड हैं बाजार की उतार-चढ़ाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उम्र 30 से 79 वर्ष तक के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अधिक प्रीमियम पर अतिरिक्त एन्युटी रेट इंसेंटिव भी उपलब्ध है।

किसके लिए उपयोगी? यह प्लान रिटायरमेंट प्लानिंग, सीनियर सिटीजन या उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो नियमित आय चाहते हैं बिना बाजार के जोखिम के। जॉइंट लाइफ विकल्प से परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। LIC की नई जीवन शांति योजना आज के अनिश्चित समय में वित्तीय स्थिरता का मजबूत सहारा साबित हो सकती है। अधिक जानकारी और उदाहरण के लिए निकटतम LIC ब्रांच या आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर संपर्क करें।

हिंदुस्तान कॉपर 5 वर्षों में खदानों के विस्तार पर खर्च करेगी 7,189 करोड़ रुपये

विजन 2030 के तहत उत्पादन क्षमता तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य, खनन क्षमता 4.21 मिलियन टन से बढ़कर 12.20 मिलियन टन सालाना

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने अगले पांच वर्षों में अपनी खदानों के विस्तार के लिए 7,189 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की योजना बनाई है। यह निवेश कंपनी के 'विजन 2030' रोडमैप का हिस्सा है, जिसके तहत कुल अयस्क उत्पादन क्षमता को मौजूदा 4.21 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12.20 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है।

कंपनी चालू वित्तीय वर्ष में 450.51 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके बाद 2027 में 1,421.73 करोड़, 2028 में 1,993.70 करोड़, 2029 में 2,227.18 करोड़ और 2030 में 1,095.48 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इस कैपेक्स से मौजूदा खदानों का विस्तार, नई परियोजनाओं का विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है।

हिंदुस्तान कॉपर वर्तमान में देश की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी है, जो खनन, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग सभी गतिविधियां संचालित करती है। बढ़ती वैश्विक मांग, इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तांबे की खपत के कारण कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है।

इस विस्तार से न केवल कंपनी की आय और लाभप्रदता में वृद्धि होगी बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित कंपनी की खदानों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीतिक निवेश भारत को तांबे के आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के अनुरूप यह योजना महत्वपूर्ण है।

हिंदुस्तान कॉपर के इस बड़े कैपेक्स प्लान से शेयर बाजार में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यदि योजना समय पर पूरी हुई तो कंपनी 2030 तक देश की तांबा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकेगी।

Rainmatter Invests ₹20 Crore in Wealth Management Startup Prime Investor

Zerodha-backed fund backs Bengaluru-based platform to strengthen retail investor education and advisory services

Bengaluru: Zerodha, has invested ₹20 crore in Prime Investor, a Bengaluru-based wealth management and investor education startup. The funding round will help Prime Investor expand its research capabilities, enhance its digital platform, and reach a wider base of retail investors across India.

Prime Investor offers independent, unbiased research reports, stock recommendations, mutual fund analysis, and comprehensive investor education content. Founded in 2020, the platform has built a strong reputation among serious retail investors for its no-nonsense, research-driven approach and transparent advisory services.

The fresh capital will be used to scale content creation, strengthen the technology backbone, and develop new tools that simplify complex investment decisions for retail participants. The company also plans to grow its team of analysts and expand into newer segments such as retirement planning and tax-efficient investing.

Rainmatter's investment reflects its continued focus on backing fintech startups that promote financial literacy and responsible investing in India. Zerodha co-founder Nithin Kamath has consistently emphasised the need for high-quality, conflict-free investment research to protect retail investors from mis-selling and poor advice.

This partnership is expected to benefit both entities. Prime Investor will gain strategic guidance and deeper market access through Rainmatter's ecosystem, while Rainmatter strengthens its portfolio in the fast-growing wealth-tech and investor education space.

With India's retail investor base expanding rapidly through SIPs and direct equity participation, demand for credible wealth management solutions is rising. Prime Investor aims to fill this gap by delivering trustworthy insights in an era of information overload and aggressive marketing by many advisory firms.

The deal underscores the growing investor interest in quality research platforms that prioritise education and long-term wealth creation over short-term trading hype.

भारतीय धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: अमेज़न ने 30 मिलियन डॉलर के कार्बन क्रेडिट खरीदे

ग्रीन राइस एलायंस के साथ समझौता, 13,000 से अधिक छोटे किसानों को आय और जलवायु संरक्षण का दोहरा लाभ

बेंगलुरु: भारतीय गेमिंग स्टार्टअप स्पिल गेम्स (Spill Games) ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 3.1 मिलियन डॉलर (लगभग 26 करोड़ रुपये) की सफलतापूर्वक राशि जुटाई है। इस राउंड का नेतृत्व सिंगापुर स्थित सेंटर कोर्ट कैपिटल ने किया, जबकि पीयरकैपिटल ने भी महत्वपूर्ण निवेश किया।

स्पिल गेम्स मुख्य रूप से मोबाइल गेमिंग पर फोकस कर रही है और कैजुअल, हाइपर-कैजुअल तथा मिड-कोर गेम्स विकसित करती है। कंपनी का लक्ष्य भारतीय युवाओं की बढ़ती गेमिंग डिमांड को पूरा करना और वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करना है।

इस फंडिंग का उपयोग कंपनी नई गेम्स के विकास, टीम विस्तार, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में करेगी। स्पिल गेम्स के फाउंडर ने कहा कि यह निवेश कंपनी

को अगले स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। उन्होंने भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री की तेजी से बढ़ती संभावनाओं पर जोर दिया।

भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता गेमिंग बाजार है, जहां मोबाइल गेमिंग का हिस्सा सबसे बड़ा है। बढ़ते स्मार्टफोन यूजर्स, सस्ता डेटा और युवा आबादी के कारण गेमिंग स्टार्टअप्स को भारी अवसर मिल रहे हैं। स्पिल गेम्स इस अवसर का फायदा उठाते हुए ई-स्पोर्ट्स और मल्टीप्लेयर गेम्स में भी कदम बढ़ा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फंडिंग से स्पिल गेम्स को प्रतिस्पर्धी बाजार में मजबूत स्थिति मिलेगी। सेंटर कोर्ट कैपिटल और पीयरकैपिटल जैसे निवेशकों का समर्थन कंपनी की विश्वसनीयता को और बढ़ाएगा। यह निवेश भारतीय गेमिंग इकोसिस्टम के लिए सकारात्मक संकेत है और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा देगा। यदि यही गति बनी रही तो भारत जल्द ही गेमिंग हब के रूप में उभर सकता है।

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	23898	25178	24890	24394	24106	23610	23322	22826
BANK NIFTY	56090	58809	58133	57111	56435	55413	54737	53715
SENSEX	77664	80622	79995	78829	78202	77036	76409	75243
FINNIFTY	26142	27565	27224	26683	26342	25801	25460	24919
MIDCAP	13732	14259	14121	13927	13789	13595	13457	13263
ACC	1411	1500	1478	1444	1422	1388	1366	1332
AXISBANK	1362	1429	1410	1386	1367	1343	1324	1300
ABCAPITAL	341	369	362	351	344	333	326	315
BHARTIARTL	1819	1917	1893	1856	1832	1795	1771	1734
BHEL	337	369	355	346	332	323	309	300
BIOCON	350	376	371	360	355	344	339	328
BEL	443	483	474	458	449	433	424	408
CDSL	1313	1472	1436	1375	1339	1278	1242	1181
DATAPATTERN	4046	5089	4639	4343	3893	3597	3147	2851
ESCORTS	3228	3497	3437	3333	3273	3169	3109	3005
EICHERMOTOR	7131	7513	7404	7268	7159	7023	6914	6778
FEDERAL BANK	293	306	302	298	294	290	286	282
GRINFRAPOJECT	867	934	916	892	874	850	832	808
HDFCBANK	785	846	830	808	792	770	754	732
HCLTECH	1203	1630	1542	1373	1285	1116	1028	859
HINDUNILVR	2325	2599	2504	2414	2319	2229	2134	2044
HAL	4271	4553	4483	4377	4307	4201	4131	4025
HYUNDAI	1781	2003	1955	1868	1820	1733	1685	1598
IOC	144	152	150	147	145	142	140	137
ICICIBANK	1326	1440	1417	1371	1348	1302	1279	1233
INFY	1155	1442	1384	1269	1211	1096	1038	923
ITC	301	318	314	308	304	298	294	288
KOTAKBNK	372	401	393	383	375	365	357	347
LICHOUSING	541	602	586	563	547	524	508	485
LT	4012	4254	4192	4102	4040	3950	3888	3798
LUPIN	2298	2484	2433	2365	2314	2246	2195	2127
MARUTI	13060	13972	13757	13409	13194	12846	12631	12283
M&M	3040	3421	3341	3191	3111	2961	2881	2731
MGL	1125	1198	1179	1152	1133	1106	1087	1060
MAZGAONDOC	2678	2918	2830	2754	2666	2590	2502	2426
PFC	469	502	490	480	468	458	446	436
RECLTD	374	406	397	385	376	364	355	343
RELIANCE	1331	1409	1391	1361	1343	1313	1295	1265
SBIN	1099	1166	1144	1121	1099	1076	1054	1031
SUNPHARMA	1619	1782	1748	1683	1649	1584	1550	1485
SHRIRAMFINANCE	1015	1136	1100	1057	1021	978	942	899
TITAN	4418	4711	4630	4524	4443	4337	4256	4150
TCS	2401	2772	2693	2547	2468	2322	2243	2097
TATAMOTORS	350	383	375	363	355	343	335	323
UPL	631	699	685	658	644	617	603	576
VALIENT	255	306	294	275	263	244	232	213
WIPRO	199	212	209	204	201	196	193	188

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.

EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in